

राजस्थान राज्य

बनाम

राजाराम

13 अगस्त, 2003

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302-हत्या-मुकदमा-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति- गवाह जिनके सामने किए गए अपराध स्वीकारोक्ति का अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण तरीके से निपटारा किया गया था-निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और मौत की सजा-उच्च न्यायालय द्वारा बरी-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: बरी करने का आदेश उचित है क्योंकि न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं है।

आपराधिक मुकदमा: एकस्ट्रा-जुडिशल कन्फेशन-एविडेंटरी वैल्यू ऑफ-होल्ड: एक न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और उचित स्थिति में की गई है मन पर भरोसा किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। संपुष्टि की आवश्यकता एक मामला है विवेक का और कानून का, एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं यह किसी न्यायालय के लिए इस धारणा के साथ शुरू करने के लिए खुला नहीं है कि यह एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-धारणा का प्रमाणिक मूल्य: दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है। यदि परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित हो जाती हैं और उन परिस्थितियों से अनुमानित किए जाने वाले प्रमुख तथ्य से निकटता से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं।

अभ्यास और प्रक्रिया: आपराधिक मामला-बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील साक्ष्य के साथ हस्तक्षेप और पुनः मूल्यांकन-अपीलीय न्यायालय का दायरा-आयोजित: जहां दोषमुक्त होने के कारण न्याय की विफलता उत्पन्न होती है, वहां हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है, जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, वहां अपीलीय न्यायालय पर साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने का कर्तव्य डाला जाता है।

शब्द और वाक्यांश:

'स्वीकारोक्ति', न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति 'और' परिस्थितिजन्य साक्ष्य '-
का अर्थ

प्रत्यर्थी-अभियुक्त पर आई. पी. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत आग्नेयास्त्र से 5 व्यक्तियों की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया था। इसकी जानकारी उसके भाई पीडब्लू 6 ने दी। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। 7 गवाहों से पूछताछ की गई। जिन परिस्थितियों पर भरोसा

किया गया, उनमें पीडब्लू 3 और 4 के सामने की गयी न्यायेतर स्वीकारोक्ति, आरोपियों को घटना के तुरंत बाद मृतक की ढाणी की तरफ से बाहर आते देखा गया, घटना के तुरंत बाद आरोपियों का आचरण संदिग्ध था, आरोपी के कपड़ों पर मानव रक्त पाया गया था और आरोपी की निशादेही पर पिस्तौल और कपड़े बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रतिवादी-अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप लगाया गया था। पी. डब्ल्यू.-6 के समक्ष भी न्यायेतर स्वीकारोक्ति दी गई थी, लेकिन गवाह ने अपने बयान में इसका खंडन किया था। अभियुक्त ने खुद को डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जांच की और पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर इस आधार पर हमला किया गया कि वे उसे गलत तरीके से फंसा रहे थे क्योंकि वे उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। मुख्य रूप से पीडब्लू 3 और 4 द्वारा दी गयी स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए और उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालाँकि, उन्हें शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे बरी कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी-राज्य ने तर्क दिया कि पीडब्लू 3 और 4 की साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं थी; और यह कि अभियुक्त पर अपराध को दृढ़ करने के लिए परिस्थितियाँ पर्याप्त थी।

प्रतिवादी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अपील बरी करने के आदेश के खिलाफ होने के कारण हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित थी।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया

1.1. कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति से संबंधित साक्ष्यों की गैर-स्वीकार्यता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो समर्थन योग्य नहीं हैं। यह असंभव है कि अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेगा जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रूप से प्रवृत्त है, और अपना अपराध स्वीकार करेगा। इसी तरह, पीडब्लू-3 पीडब्लू-4 का एक करीबी रिश्तेदार है और जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिस्ट्रीशीटर होने के कारण संदिग्ध पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। हालाँकि यह अकेला उसकी साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों की समग्रता उसके साक्ष्य पर संदेह की एक अमिट छाया डालती है। हालाँकि यह अभियोजन पक्ष का संस्करण था कि सूचना देने वाले के सामने न्यायेतर स्वीकारोक्ति भी हुयी थी, जिसे निचली अदालत

और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया था कि उसने जांच के दौरान कथित रूप से जो कहा था उससे अलग कहा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी ने उनके सामने कोई इकबालिया बयान दिया था। यद्यपि अभियुक्त (डी. डब्ल्यू.-1) की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया कि उसने पी. डब्ल्यू.-6 के समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति दी थी, लेकिन पी. डब्ल्यू.-3 और 4 के संबंध में ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था।

1.2. फॉरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट से पता चला कि आरोपियों की शर्ट और पतलून पर मानव रक्त के धब्बे थे। रक्त समूह का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर गौर किया और पाया कि बरामदगी के समय पीडब्लू-4 की उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि उसे एक अविश्वसनीय गवाह पाया गया है। यह देखा गया कि भले ही यह स्वीकार किया जाए कि खून का अस्तित्व था, लेकिन यह स्थिति ऐसी नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ही अपराध का अपराधी था। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कपड़ों पर पाए गए रक्त से रक्त समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका था। न तो मृतक का रक्त समूह पता चला और न ही आरोपी का।

1.3. कथित तौर पर आरोपी की निशादेही पर जो पिस्तौल बरामद की गयी, वह वही पिस्तौल नहीं पायी गयी, जिससे शवों पर लगी गोलियां चलायी गयी थी।

2.1. स्वीकारोक्ति की साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिससे यह किया गया है। स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य का मूल्य साक्ष्य देने वाले गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। किसी भी न्यायालय के लिए यह धारणा शुरू करना संभव नहीं है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार की साक्ष्य है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, कब स्वीकारोक्ति की गई थी और इस तरह के स्वीकारोक्ति की बात करने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। इस तरह के कबूलनामे पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है। यदि कबूलनामे के बारे में साक्ष्य गवाह के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होता है, यहां तक कि आरोपी के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं है, और जिसके संबंध में कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जो यह संकेत दे सकता है कि उसका उद्देश्य आरोपी को एक असत्य बयान देने के लिए हो सकता है, गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि आरोपी अपराध का अपराधी है और गवाह द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी

पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। पुष्टि की आवश्यकता विवेक का विषय है न कि कानून का कोई अपरिवर्तनीय नियम।

2.2. स्वीकारोक्ति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् न्यायिक और न्यायेत्तर। न्यायिक स्वीकारोक्ति वे हैं जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किए जाते हैं। न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति वे हैं जो पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के अलावा कहीं और किए जाते हैं। न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति आम तौर पर वे होते हैं जो एक पक्ष द्वारा किसी निजी व्यक्ति के सामने या उसके सामने किए जाते हैं जिसमें एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होता है। इसमें एक मजिस्ट्रेट भी शामिल है, जो विशेष रूप से संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए सशक्त नहीं है या एक मजिस्ट्रेट इतना सशक्त है। लेकिन एक स्तर पर स्वीकारोक्ति प्राप्त करना जब धारा 164 लागू नहीं होती है। एक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक होगी यदि यह अभियुक्त द्वारा मन की स्वस्थ स्थिति में किया जाता है, और यदि यह किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण नहीं होता है जो उसके खिलाफ आरोप का संदर्भ देता है, जो किसी अधिकार में किसी व्यक्ति से आगे बढ़ता है। स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी या

नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसका निर्णय धारा 24 के आलोक में किया जाएगा।

2.3. एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति उच्चतम श्रेय के योग्य है। क्योंकि यह माना जाता है कि यह अपराध की उच्चतम भावना से प्रवाहित होता है। यह कल्पना नहीं की जानी चाहिए कि अगर स्वीकार किए गए तथ्य सच नहीं थे, तो किसी को अपराध की स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो मानव स्वभाव की भावना और सिद्धांतों के विपरीत है। जानबूझकर और स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करना, यदि स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है, तो कानून में सबसे प्रभावी सबूतों में से एक हैं। अनैच्छिक स्वीकारोक्ति वह है जो इसके निर्माता की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं है। अतः जहाँ व्यक्ति को अपराधी और अभियुक्त माने जाने के बाद कई घंटों तक उत्पीड़न और निरंतर पूछताछ के परिणामस्वरूप बयान दिया जाता है, वहाँ इस तरह के बयान को अनैच्छिक माना जाना चाहिए। प्रलोभन एक वादे या धमकी का रूप ले सकता है, और अक्सर प्रलोभन में वादा और धमकी दोनों शामिल होते हैं, यदि खुलासा किया जाता है तो माफी का वादा और यदि ऐसा नहीं होता है तो मुकदमा चलाने की धमकी दी जाती है।

आर. बनाम वारविकशॉल, (1783) लेशी 263, का उल्लेख किया गया है।

वुड्रॉफी एविडेंस, 9 वां संस्करण पी. 284, संदर्भित।

2.4. एक वादा हमेशा स्वीकारोक्ति विकल्प से जुड़ा होता है, जबकि एक खतरा हमेशा मौन विकल्प से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रलोभन, धमकी या वादा किसी स्वीकारोक्ति को दूषित नहीं करता है। चूँकि नियम का उद्देश्य केवल उन स्वीकारोक्ति को बाहर करना है जो प्रमाणिक रूप से अविश्वसनीय हैं, प्रलोभन, धमकी या वादा ऐसा होना चाहिए जिसकी गणना एक असत्य स्वीकारोक्ति की ओर ले जाने के लिए की जाती है। यदि अदालत की राय में प्रलोभन, वादा या धमकी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे आधार देने के लिए पर्याप्त है जो उसे उचित लगेंगे, यह मानते हुए कि ऐसा करने से वह कोई लाभ प्राप्त करेगा या किसी बुराई से बच जाएगा, तो स्वीकारोक्ति को बाहर करने के लिए पर्याप्त है। खंड के अंतिम भाग में 'उसे दिखाई देता है' शब्द अभियुक्त की मानसिकता को संदर्भित करते हैं।

3.1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है-लेकिन इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 343 और शरद बर्धीचंद सारदा बनाम।

महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. (1984) एस. सी. 1622 पर भरोसा किया गया।

3.2. जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां अपराध के अनुमान को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पायी जाये। जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही को नकारात्मक करे दे और अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे कर दे।

हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 1063; एराडू और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316; एरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य ए. आई. आर. (1983) एससी 446; यू. पी. राज्य बनाम सुखबासी और अन्य ए.आई.आर. (1985) एससी 1224; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. (1987) एससी 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम. पी. राज्य ए.आई.आर. (1989) एस. सी. 1890; सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम ए. पी. राज्य

[1996] 10 एस. सी. सी. 193; पदाला वीरा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य और अन्य। ए.आई.आर. (1990) एस. सी. 79 और यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (1992) सीआरएल। एल. टी. 1104, संदर्भित।

सर अल्फ्रेड विल्स द्वारा विल्स के परिस्थितिजन्य साक्ष्य। का उल्लेख किया गया है।

4. अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिन पर दोषमुक्त करने का आदेश आधारित है। आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्दोष होने का अनुमान बरी होने से और मजबूत होता है। आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो एक अभियुक्त का अपराध और दूसरा उसकी निर्दोषता के लिए, वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के पक्ष में हो, अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, अपीलीय न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि वह ऐसे मामले में साक्ष्य की फिर से सराहना करे जहां अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है, यह पता लगाने के

उद्देश्य से कि क्या कोई अभियुक्त ने कोई अपराध किया है या नहीं। बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत का पालन केवल तभी किया जाना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों। यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है, तो यह हस्तक्षेप का एक सम्मोहक कारण है।

शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य । [1973] 3 एस. सी. सी. 193 और रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य [1996] 9 एस. सी. सी. 225 और जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जे. टी. (2000) 4 एस. सी. 114, पर निर्भर था।

भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जे. टी. (2002) 3 एस. सी. 3871, संदर्भित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं 815-816/1996

राजस्थान उच्च न्यायालय डी. बी. सी. आर. एल. ए. सं. 395 और 404/1995 में डी. बी. हत्या संदर्भ सं. 3/95 निर्णय और आदेश के दिनांक 29.2.96 के से।

आलोक बच्चन, वी. एन. रघुपति के लिए सुश्री भारती उपाध्याय और अपीलार्थी के लिए महिंदर सिंह दहिया (एन. पी.)।

इंगर सिंह, सुशील के. जैन एच. डी. थानवी और अनिल व्यास उत्तरदाता।

राजस्थान राज्य की अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी निर्दोष था और भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में आई.पी.सी.) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के कथित अपराध के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी होने का हकदार था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हनुमानगढ़ द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया गया, जिन्होंने आरोपी को दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई।

अभियोजन मामले की नींव रखने वाले आरोपों से पता चलता है कि सही राम (पीडब्लू-6) द्वारा 20-12-1989 को सुबह लगभग 7.15 बजे संगरिया पुलिस स्टेशन में इस आशय की जानकारी दी गई थी कि उसका छोटा भाई 5 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। यानी उसके पिता, छोटा भाई, छोटे भाई की पत्नी और उनके दो बच्चे। हत्याएं बंदूक की गोली के कारण हुईं और हत्याएं 19-12-1989 को की गईं, जिस पर दर्ज की गई जानकारी के आधार पर जांच की गई और उसके पूरा होने पर आरोप पत्र

दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि आईपीसी की धारा 302 और भारतीय शस्त्र अधिनियम ए 1959 की धारा 27 (संक्षेप में 'शस्त्र अधिनियम') के तहत दंडनीय अपराध किए गए थे, अपीलकर्ता काे हमलावर के रूप में वर्णित किया गया था। अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए 7 गवाहों से पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष का कथन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। आरोपी ने खुद की जांच डीडब्ल्यू.1 के रूप में की और पीडब्ल्यू.3 और 4 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता पर हमला करने के लिए रिकॉर्ड सामग्री रखी, विशेष रूप से यह कहा गया कि उनका उसके प्रति अनुकूल रुख नहीं था और उन्होंने उसे झूठा फंसाया था। विनोद कुमार (पीडब्लू.3) और नंद राम (पीडब्लू.4) के बयान को स्वीकार करते हुए, जिनके समक्ष कथित तौर पर आरोपी ने अतिरिक्त न्यायिक बयान दिया था, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि मौत की सजा सुनाई आैर 5000 रुपये के जुर्माने के अलावा मौत की सजा सुनाई। हालाँकि, यह पाया गया कि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 से संबंधित आरोप स्थापित नहीं हुए थे। चूंकि मौत की सजा सुनाई गई है, इसकी पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया था। एक आरोपी ने अपील भी दायर की थी अपील में, जैसा कि दहलीज पर उल्लेख किया

गया है, उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी पर दोष सिद्ध करने के लिए सबूत अपर्याप्त थे और इसलिए, अभियोजन पक्ष का संस्करण कमजोर था। पीडब्लू.3 और पीडब्लू.4 की साक्ष्य, जो ट्रायल कोर्ट के फैसले का आधार बने, को उच्च न्यायालय ने सबूतों को अविश्वसनीय और असंगत पाते हुए स्वीकार नहीं किया।

अपीलकर्ता के लिए राज्य के विद्वान वकील ने अपील के समर्थन में कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है। पीडब्लू.3 और पीडब्लू.4 की साक्ष्य में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी, जिससे उनकी साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सके। वे आरोपी और मृतक दोनों से संबंधित थे और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे आरोपी को झूठा क्यों फंसाएंगे। अभियुक्त का आचरण, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा संदिग्ध पाया गया था, को बरी करने का निर्देश देते समय उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। अभियुक्तों के पहने हुए कपड़ों पर खून के धब्बे थे और चूंकि अभियुक्त ने यह नहीं बताया कि ऐसे कपड़ों पर खून के धब्बे कैसे दिखाई दिए, यह अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति है, जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया।

अभियुक्त पर दोष सिद्ध करने के लिए उजागर की गई परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं:-

(1) गवाहों के समक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की न्यायेतर स्वीकारोक्ति।

(2) घटना के तुरंत बाद आरोपी मृतक मनीराम की ढाणी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया।

(3) घटना के तुरन्त बाद अभियुक्त का आचरण।

(4) अभियुक्त के कपड़ों पर मानव रक्त पाया जाना।

(5) अभियुक्त द्वारा कराई गई पिस्तौल की बरामदगी।

यह नोट किया गया है कि परिस्थितियाँ 1, 2 और 3 गवाह पीडब्ल्यू 3 और 4 की साक्ष्य से संबंधित हैं। कथित तौर पर अभियुक्त द्वारा इंगित किए जाने पर जो पिस्तौल बरामद की गई थी, वह वह नहीं थी, जिससे शवों पर मिली गोलियाँ चलाई गई थीं।

प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और उजागर की गयी परिस्थितियों की श्रृंखला पर आधारित है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपरिहार्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया, जिसे खारिज कर दिया और यह स्थापित किया कि केवल अभियुक्त ही अपराध के लिए जिम्मेदार था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपील बरी करने के आदेश के खिलाफ है, हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। पीडब्ल्यू-3 और 4 के साक्ष्य को सही

ढंग से खारिज कर दिया गया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय के तर्कसंगत फैसले में हस्तक्षेप किया जाए।

अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है। आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि बरी होने से आरोपी की बेगुनाही की धारणा और भी मजबूत हो जाती है। आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में जो सुनहरा धागा चलता है, वह यह है कि यदि मामले में पेश किए गए सबूतों पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो आरोपी के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। दोषियों को बरी करने से होने वाली न्याय की हानि किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अपीलीय अदालत पर यह कर्तव्य बनता है कि वह उस मामले में साक्ष्य की फिर से सराहना करे, जहां आरोपी को बरी कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी आरोपी ने कोई अपराध किया है या नहीं। [देखें भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जेटी (2002) 3 एससी 387] दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय

न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाला सिद्धांत केवल तभी हस्तक्षेप करना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है, तो यह हस्तक्षेप का एक अनिवार्य कारण है।

शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [1973] 3 एससीसी 193, रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य [1996] 9 एससीसी 225 और जसवन्त सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जेटी (2000) 4 एससी 114

तथ्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने से पहले यह कहा जा सकता है कि किसी अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध को घटित होते हुए देखा जाए और सभी परिस्थितियों में अदालत के समक्ष उन व्यक्तियों की जांच करके प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए जिन्होंने अपराध किया था। इसका अपराध देखा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अपराध साबित किया जा सकता है। मुख्य तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को अप्रत्यक्ष रूप से फैक्टम प्रोबन्स, यानी साक्ष्यात्मक तथ्यों से निकाले गए कुछ निष्कर्षों के माध्यम से साबित किया जा सकता है। इसे अलग ढंग से कहें तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुद्दे के मुद्दे पर प्रत्यक्ष नहीं होते हैं बल्कि इसमें विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य शामिल होते हैं जो मुद्दे के तथ्य के साथ इतनी निकटता से जुड़े होते हैं

कि एक साथ मिलकर वे परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिससे मुख्य तथ्य का अस्तित्व संभव हो सकता है। कानूनी तौर पर अनुमान या अनुमान लगाया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं।

(हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1977) एससी 1063; एराडु और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य, एआईआर (1956) एससी 316; ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर (1983) एससी 446; यूपी राज्य बनाम सुखबासी और अन्य, एआईआर (1985) एससी 1224; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1987) एससी 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम एमपी राज्य, एआईआर (1989) एससी 1890)। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित करना होगा और उन परिस्थितियों से अनुमानित किए जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1954) एससी 621; में, यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों

से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही को नकारात्मक कर दे और अपराधों को किसी भी उचित संदेह से परे कर दे।

हम इस मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [1996] 10 एससीसी 193, का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर (1990) एससी 79, में यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए :

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।

(2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों।

(3) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों की एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं; और

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होनी चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसी साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होनी चाहिए बल्कि असंगत भी होनी चाहिए। यूपी राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव [1992] सीआर.एलजे 1104) में यह बताया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि साक्ष्य दो निष्कर्षों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया

जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव सुसंगत होना चाहिए।

सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक "विल्स सर्कमस्टेंसियल एविडेंस" (अध्याय VI) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रूप से पालन किए जाने वाले निम्नलिखित नियम बताए हैं: (1) किसी भी कानूनी निष्कर्ष के आधार के रूप में कथित तथ्यों को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे जोड़ा जाना चाहिए। (2) सबूत का बोझ हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाता है; (3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है, (4) अपराध के अनुमान को उचित ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्य अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए, (5) यदि अभियुक्त के अपराध पर कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने के अधिकार का हकदार है।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसे 1952 में इस न्यायालय द्वारा

निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1952) एससी 343, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया था:

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति की है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें प्रथम दृष्टया पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो साबित होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक श्रृंखला अब तक पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1984) एससी 1622, के मामले में बाद के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के दौरान, यह माना गया है कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर था कि श्रृंखला पूरी है और अभियोजन में कमी की कमजोरी को झूठे बचाव या दलील से ठीक नहीं किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि करने से पहले, इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। वे से प्रकार है:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभवनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

मौजूदा मामले को उपरोक्त सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में जांचा जाना चाहिए। पीडब्लू.3 और 4 की साक्ष्य, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभियोजन मामले की नींव बनाते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया कि पीडब्लू.4 के अभियुक्त के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वास्तव में, घटना से कुछ महीने पहले अभियुक्त द्वारा पीडब्लू.4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

इकबालिया बयान को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी न्यायिक और न्यायेतर। न्यायिक संस्वीकृति वे हैं जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष की जाती हैं। न्यायेतर स्वीकारोक्ति वे हैं जो किसी पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कहीं और किए जाती हैं। न्यायेतर स्वीकारोक्ति आम तौर पर किसी पक्ष द्वारा किसी निजी व्यक्ति के समक्ष या उसके समक्ष की गई स्वीकारोक्ति होती है, जिसमें उसकी निजी क्षमता में एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होता है। इसमें एक मजिस्ट्रेट भी शामिल है जो विशेष रूप से संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए सशक्त नहीं है या एक

मजिस्ट्रेट इतना सशक्त है लेकिन उस चरण में बयान प्राप्त कर रहा है जब धारा 164 लागू नहीं होती है। जहाँ तक न्यायेतर स्वीकारोक्ति का सवाल है, दो प्रश्न उठते हैं: (i) क्या वे स्वेच्छा से बनाए गए थे? और (ii) क्या वे सच हैं? जैसा कि धारा अधिनियमित करती है, किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा किया गया इकबालिया बयान आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि अदालत को बयान देना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण हुआ प्रतीत होता है, (1) अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप का संदर्भ है, (2) किसी प्राधिकारी व्यक्ति से कार्यवाही करना, और (3) न्यायालय की राय में आरोपी व्यक्ति को ऐसे आधार देने के लिए पर्याप्त है जो उसे यह मानने के लिए उचित लगे कि ऐसा करने से उसे कोई लाभ मिलेगा या उसके विरुद्ध कार्यवाही के संदर्भ में अस्थायी प्रकृति की किसी भी बुराई से बचें। इसका तात्पर्य यह है कि एक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक होगी यदि यह अभियुक्त द्वारा मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में किया गया है, और यदि यह किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण नहीं होता है जो उसके खिलाफ आरोप का संदर्भ देता है, जो कि अधिकार में किसी व्यक्ति से आगे बढ़ता है। यह अनैच्छिक नहीं होगा, यदि प्रलोभन, (क) आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप का संदर्भ नहीं है, या (ख) यह किसी अधिकारी व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ता है; या (ग) न्यायालय की राय में आरोपी व्यक्ति को ऐसे आधार देना पर्याप्त नहीं है जो उसे यह मानने के लिए उचित लगे कि ऐसा करने से उसे कोई

लाभ मिलेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में लौकिक प्रकृति की किसी भी बुराई से बच जायेगा। उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसका निर्णय धारा 24 के आलोक में किया जाएगा। कानून स्पष्ट है कि किसी स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि यह स्वैच्छिक था और उस स्तर पर यह सवाल नहीं उठता कि यह सच है या गलत। यदि संस्वीकृति देने से जुड़े तथ्य और परिस्थितियाँ संस्वीकृति की सत्यता या स्वैच्छिकता पर संदेह उत्पन्न करती प्रतीत होती हैं, तो न्यायालय संस्वीकृति पर कार्रवाई करने से इंकार कर सकता है, भले ही वह साक्ष्य में स्वीकार्य हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके संबंध में न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि क्या जब अभियुक्त ने इकबालिया बयान दिया था, तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति था या उसकी हरकतों को पुलिस द्वारा या तो स्वयं या ऐसी स्वीकारोक्ति हासिल करने के उद्देश्य से उनके द्वारा नियोजित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से नियंत्रित किया गया था। यह प्रश्न कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है या नहीं, सदैव तथ्य का प्रश्न है। मामले के सभी कारकों और सभी परिस्थितियों, जिनमें विचार के लिए दिए गए समय के महत्वपूर्ण कारक अभियुक्त को धमकी, प्रलोभन या वादे की भावना मिलने की गुंजाइश शामिल है, पर

निर्णय लेने से पहले विचार किया जाना चाहिए कि क्या न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसकी राय प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण उत्पन्न धारणा, यदि कोई हो, पूरी तरह से हटा दी गई है। एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति सर्वोच्च श्रेय की पात्र है, क्योंकि यह अपराध की उच्चतम भावना से उत्पन्न माना जाता है। [देखें आर.वी. वारविकशालर, (1783) लेस्च 263। यह कल्पना नहीं की जानी चाहिए कि यदि स्वीकार किए गए तथ्य सत्य नहीं हैं, तो किसी व्यक्ति को अपराध की स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो मानव स्वभाव की भावनाओं और सिद्धांतों के विपरीत है। जानबूझकर और स्वैच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति, यदि स्पष्ट रूप से साबित हो, कानून में सबसे प्रभावशाली सबूतों में से एक है। एक अनैच्छिक स्वीकारोक्ति वह है जो इसे करने वाले की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं है। इसलिए जहां व्यक्ति को अपराधी और आरोपी मानने के बाद कई घंटों तक उत्पीड़न और लगातार पूछताछ के परिणामस्वरूप बयान दिया जाता है, ऐसे बयान को अनैच्छिक माना जाना चाहिए। प्रलोभन एक वादे या धमकी का रूप ले सकता है, और अक्सर प्रलोभन में वादा और धमकी दोनों शामिल होते हैं, यदि खुलासा किया जाता है तो माफी का वादा और यदि ऐसा नहीं होता है तो मुकदमा चलाने की धमकी दी जाती है। (देखें वुडरोफ़ साक्ष्यए 9 वां संस्करण पृष्ठ 284)। एक वादा हमेशा स्वीकारोक्ति, विकल्प से जुड़ा होता है जबकि एक

धमकी हमेशा मौन विकल्प से जुड़ी होती है। इस प्रकार, एक मामले में कैदी वादे के शुद्ध लाभ को माप रहा है, वर्तमान असंतोषजनक स्थिति के मुकाबले, झूठी स्वीकारोक्ति की सामान्य अवांछनीयता को घटाकर। जबकि दूसरे मामले में वह वर्तमान संतोषजनक स्थिति के शुद्ध लाभों को माप रहा है, खतरे की हानि के विरुद्ध स्वीकारोक्ति की सामान्य अवांछनीयता को घटाकर। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रलोभन, धमकी या वादा किसी स्वीकारोक्ति को खराब नहीं करता है। चूँकि नियम का उद्देश्य केवल उन स्वीकारोक्ति को बाहर करना है जो प्रशंसापत्र रूप से अविश्वसनीय हैं, प्रलोभन, धमकी या वादा ऐसा होना चाहिए जो असत्य स्वीकारोक्ति की ओर ले जाए। उपरोक्त विश्लेषण पर न्यायालय को प्रलोभन, वादे आदि की अनुपस्थिति या उपस्थिति या इसकी पर्याप्तता का निर्धारण करना है और इसने अभियुक्त के दिमाग पर कैसे या किस मात्रा में काम किया है। यदि न्यायालय की राय में प्रलोभन, वादा या धमकी पर्याप्त है, तो आरोपी व्यक्ति को ऐसे आधार देने के लिए जो उसे यह मानने के लिए उचित लगे कि ऐसा करने से उसे कोई लाभ मिलेगा या किसी बुराई से बचा जा सकेगा, यह स्वीकारोक्ति को बाहर करने के लिए पर्याप्त है। खण्ड के अंतिम भाग में 'उसे प्रतीत होता है' शब्द अभियुक्त की मानसिकता को दर्शाते हैं।

एक न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सच्ची है और मन की उपयुक्त स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा

सकता है। किसी भी अन्य तथ्य की तरह इस स्वीकारोक्ति को भी साबित करना होगा। स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिससे यह किया गया है। स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य का मूल्य साक्ष्य देने वाले गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। किसी भी न्यायालय के लिए यह धारणा शुरू करना संभव नहीं है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, कबूलनामे के समय और ऐसे बयान देने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। इस तरह की स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है यदि स्वीकारोक्ति के बारे में साक्ष्य उन गवाहों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, अभियुक्त के लिए दूर-दूर तक भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जो यह इंगित करने की प्रवृत्ति रखता है कि उसके पास आरोपी पर असत्य बयान देने का मकसद हो सकता है, गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आरोपी अपराध का अपराधी है और गवाह द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। गवाह की साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद, न्यायेतर स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता

है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

यदि न्यायेतर संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य को विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर परखे जाने के बाद विश्वसनीय पाया जाता है, तो यह पूरी तरह से सजा का आधार बन सकता है। प्रतिवादी-अभियुक्त के लिए विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत की गई पुष्टि की आवश्यकता, विवेक का विषय है न कि कानून का एक अपरिवर्तनीय नियम। यह असंभव है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अभियुक्त उस व्यक्ति पर भरोसा करेगा जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रूप से प्रवृत्त है, और अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। इसी तरह, पीडब्लू.3, पीडब्लू.4 का करीबी रिश्तेदार है और जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, संदिग्ध पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति हिस्ट्रीशीटर है। हालाँकि यह अकेला उसके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, परिस्थितियों की समग्रता उसके साक्ष्य पर संदेह की अमिट छाया डालती है। यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी ने खुद को डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में जांचा। हालाँकि यह अभियोजन पक्ष का कथन था कि मुखबिर सही राम (पीडब्लू.6) के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तथ्य के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया था कि उसने जांच के दौरान कथित तौर पर जो कहा था, उससे अलग तरीके से कहा था। उन्होंने इस

बात से इनकार किया कि आरोपी ने उनके सामने कोई इकबालिया बयान दिया है। हालाँकि अभियुक्त (डीडब्ल्यू.1) की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया कि उसने पीडब्लू.6 के समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति की थी, लेकिन पीडब्लू.3 और 4 के संबंध में ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था। आरोपी द्वारा बताए जाने पर कथित तौर पर जो कपड़ा जब्त किया गया था, फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आरोपी के शर्ट और पतलून पर मानव रक्त के धब्बे थे। ब्लड ग्रुप जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर गौर किया और पाया कि बरामदगी के समय पीडब्लू.4 की उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि उसे एक अविश्वसनीय गवाह पाया गया है। यह देखा गया कि अगर यह मान भी लिया जाए कि खून का अस्तित्व था, तो भी यह परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि आरोपी अपराध का अपराधी था। उपरोक्त रिपोर्ट (एक्स 61) में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कपड़ों पर पाए गए रक्त का रक्त समूह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। न तो मृतक का ब्लड ग्रुप पता चला और न ही आरोपी का। उस पृष्ठभूमि में] उच्च न्यायालय ने माना कि खून आरोपी का होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति से संबंधित साक्ष्यों की गैर-स्वीकार्यता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को

अप्राप्य नहीं कहा जा सकता है। हम अपीलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निखिल सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।